



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूर और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित



5 बुमराह से मिली हौसला-अफजाई से चोटों से उबरने में मदद मिली श्रेयंका को

6 गिग-वर्कर्स की परेशानियों को समझना आवश्यक

7 पर्दे पर फिर लौट रही सैयामी खेर

फ़र्स्ट टेक

दो करोड़ की लागत से तैयार 'सुवर्ण गीता' का आज उड़पी में विमोचन उड़पी (कर्नाटक)/भाषा। पुत्रिगे मठ के महंत सुगणेन्द्र तीर्थ भीपद द्वारा दो करोड़ रुपये की लागत से तैयार 'सुवर्ण गीता' के एक विशाल संस्करण का बृहस्पतिवार को यहां औपचारिक अनावरण किया जाएगा। बुधवार को यहां मठ द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। विज्ञप्ति के मुताबिक, 'सुवर्ण गीता' का विमोचन श्री व्यासराज मठ के श्री विद्याभीशीर्ष भीपद करेंगे। इस 'सुवर्ण गीता' को तैयार करने में दिल्ली के कृष्ण भक्त और केंद्रीय गृह मंत्रालय के पूर्व सचिव लक्ष्मी नारायणन ने आर्थिक मदद दी है। करीब दो करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस पवित्र ग्रंथ को 'कोटि गीता लेखन यज्ञ' के उपलक्ष्य में भेंट किया जाएगा। विज्ञप्ति के मुताबिक, इस कार्यक्रम के तहत 'सुवर्ण गीता' को सोने के रथ पर रखा जाएगा और एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसके बाद राजनगना में एक औपचारिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

26 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा/भाषा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 26 माओवादियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 13 पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम है। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की 'छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति' के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुकमा पुलिस 'पूना मार्ग' पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान चला रही है। इससे प्रभावित होकर तथा अति संवेदनशील अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार शिविर स्थापित होने से पुलिस के बढ़ते प्रभाव से माओवादी संगठन में सक्रिय सात महिला सहित 26 माओवादियों ने आज सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चट्टाण और सुरक्षाबलों के वरिष्ठ अधिकारियों सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

'धुरंधर' ने अब तक

कमाए 831 करोड़

मुंबई/भाषा। फिल्म निर्माता आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' देशभर में कुल 831 करोड़ रुपए से अधिक का व्यवसाय करते हुए अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। फिल्म निर्माताओं ने बुधवार को यह जानकारी दी। निर्माताओं ने बताया कि रणवीर सिंह अभिनीत इस फिल्म ने रिलीज के 33वें दिन मंगलवार को 5.70 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसके बाद इसकी देशभर में कुल कमाई बढ़कर 831.40 करोड़ रुपए हो गई। इसके साथ ही यह अब तक की सभी हिंदी फिल्मों में पहले स्थान पर पहुंच गई।

08-01-2026
सूर्योदय 6:08 बजे

09-01-2026
सूर्यास्त 6:44 बजे

BSE 84,961.14
(+102.20)

NSE 26,140.75
(-37.95)

सोना 14,238 रु.
(24 रु.) प्रति ग्राम

चांदी 251,328 रु.
प्रति किलो

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com



कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

अस्थाई राज

इतनी भी नाराजी क्यों हैं, सत्ता तो आनी-जानी। ऐसी भाषा बोल रहे क्यों, जैसे हो दुश्मन जानी। बोलो कब ठहरा है अब तक, बहती नदिया का पानी। लोकतंत्र में नहीं चलेगी, कभी किसी की मनमानी।।

भारत के 'सुधारों की एक्सप्रेस' पकड़ रही है रफ्तार : प्रधानमंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वित्त वर्ष 2025-26 में आर्थिक वृद्धि दर के 7.4 प्रतिशत रहने के अनुमान पर बुधवार को कहा कि राजग सरकार की निवेश नीतियों के चलते भारत की 'सुधार एक्सप्रेस' रफ्तार पकड़ रही है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "भारत की सुधार एक्सप्रेस लगातार रफ्तार पकड़ रही है। यह राजग सरकार के व्यापक निवेश प्रोत्साहन और मांग-आधारित नीतियों के कारण संभव हो पा रहा है।"

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की तरफ से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। यह भारतीय

'परीक्षा पे चर्चा' में छात्रों से संवाद के लिए उत्सुक हूं



नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वह वार्षिक परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ परीक्षाओं के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं।

प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि वह परीक्षा योद्धाओं से ऐसे सवाल और

अनुभव सुनने के लिए उत्सुक हैं, जो दूसरों को प्रेरित कर सकें। उन्होंने कहा, दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं और इस साल की परीक्षा पे चर्चा भी।

प्रधानमंत्री ने कहा, परीक्षाओं के विभिन्न पहलुओं पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं, विशेष रूप

रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 7.3 प्रतिशत के अनुमान और सरकार के शुरूआती अनुमान 6.3 से 6.8 प्रतिशत से बेहतर है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "चाहे वह बुनियादी ढांचा हो, विनिर्माण प्रोत्साहन हो, डिजिटल सार्वजनिक उत्पाद हों या

से परीक्षा के तनाव को दूर करने के तरीकों, शांत और आत्मविश्वासी बने रहने और मुश्कुराते हुए परीक्षा देने के तरीकों पर। भारत और 26 देशों से लगभग 45 लाख उम्मीदवारों के कक्षा 10वीं और 12वीं के 204 विषयों में परीक्षा के लिए शामिल होने के उम्मीद हैं। सीबीएसई की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होने की संभावना है।

'परीक्षा पे चर्चा' के नौवें संस्करण के लिए 375 करोड़ छात्रों सहित चार करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। 'परीक्षा पे चर्चा' के लिए पंजीकरण 11 जनवरी को समाप्त होगा।।

'कारोबारी सुगमता', हम एक समृद्ध भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं।"

एसआईआर का दूसरा चरण

12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से

करीब 6.5 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए

नई दिल्ली/भाषा। निर्वाचन आयोग द्वारा नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) के तहत करीब 6.5 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 27 अक्टूबर को एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी और तब कुल 50.90 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे। हालांकि अलग-अलग प्रकाशित मसौदा मतदाता सूचियों में मतदाताओं की संख्या घटकर 44.40 करोड़ रह गई है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि जिन लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं, उन्हें 'एसडी' यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत/नाम में दोहराव की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने पहले उपलब्ध रजामों का हवाला देते हुए कहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में गणना प्रपत्रों का संग्रह 'काफी कम' रहा है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के बाद मंगलवार को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इसके मुताबिक राज्य में अब 12.55 करोड़ मतदाता हैं। आयोग ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पहले सूचीबद्ध 15.44 करोड़ मतदाताओं में से 2.89 करोड़ (करीब 18.70 प्रतिशत) मतदाताओं के नाम मृत्यु, स्थायी प्रवास या एकाधिक पंजीकरण के कारण मसौदा सूची में शामिल नहीं किए जा सके।

वैश्विक राजनीति को स्थिर करने के लिए

भारत, फ्रांस को मिलकर

काम करना चाहिए : जयशंकर

नई दिल्ली/भाषा। दुनिया में उथल-पुथल वाले भू-राजनीतिक माहौल के मद्देनजर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि वैश्विक राजनीति को स्थिर करने के लिए भारत और फ्रांस का साथ मिलकर काम करना महत्वपूर्ण हो गया है। विदेश मंत्री ने पेरिस में अपने फ्रांसीसी समकक्ष ज्यां-नोएल बैरोट के साथ बैठक के दौरान यह टिप्पणी की। दोनों विदेश मंत्रियों ने मुख्य रूप से एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले महीने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की भारत यात्रा के लिए आधार तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया।

2027 की जनगणना का पहला चरण अप्रैल से सितंबर के बीच होगा

नई दिल्ली/भाषा। जनगणना 2027 का पहला चरण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घरों की सूची बनाने के अभियान के साथ इस वर्ष एक अप्रैल से 30 सितंबर के बीच होगा। बुधवार को जारी एक सरकारी

अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। इस दौरान, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 30 दिन की अवधि निर्दिष्ट की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि घरों की सूची बनाने का 30

दिन का अभियान शुरू होने से ठीक पहले 15 दिनों की अवधि में स्व-गणना कराने का विकल्प भी होगा। हर दस वर्षों में होने वाली जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। यह पहले 2021 में

होनी थी। जनगणना करने की यह कवायद दो चरणों में संपन्न की जाएगी -- अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों की सूची बनाना और आवास गणना, और फरवरी 2027 में आबादी की गणना।

वेनेजुएला के तेल टैंकरों पर किया

अमेरिका ने कब्जा

वॉशिंगटन/एपी। अमेरिका ने

उत्तरी अटलांटिक और कैरेबियन में एक के बाद एक की गई दो कार्रवाइयों में वेनेजुएला से जुड़े दो प्रतिबंधित तेल टैंकरों को जव्त कर लिया। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अमेरिकी-यूरोपीय कमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में 'अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन' के आरोप में व्यापारिक पोत बेला-1 को जव्त करने की घोषणा की। अमेरिका पिछले महीने से इस टैंकर का पीछा कर रहा था, क्योंकि इसने वेनेजुएला के आसपास प्रतिबंधित तेल जहाजों पर अमेरिकी नाकेबंदी से बचने की कोशिश की थी। इसके बाद, अमेरिका की गृह मंत्री क्रिस्टी नोएम ने खुलासा किया कि अमेरिकी सेना ने कैरिबियन में टैंकर सोफिया पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया है। नोएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों जहाज 'या तो आखिरी बार वेनेजुएला में रुके थे या उसकी ओर जा रहे थे।' एक अमेरिकी अधिकारी ने बुधवार को एसोसिएटेड प्रेस को पहचान जाहिर नहीं होने के अनुरोध के साथ बताया कि अमेरिकी सेना ने बेला-1 को जव्त कर लिया और बाद में इसका नियंत्रण कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सौंप दिया।



दिल्ली में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान भीड़ हुई बेकाबू

■ अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान कथित तौर पर 30-35 लोगों के एक समूह ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए, बैरिकेड तोड़े और एक लाउड स्पीकर छीनकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया।

■ एक नाबालिग समेत पांच लोगों को हिरासत में लिया गया और 10-15 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।

शामिल पुलिस अधिकारियों और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अधिकारियों पर पथराव करने में 100 से अधिक प्रदर्शनकारी शामिल थे। इस दौरान एक नाबालिग समेत पांच लोगों को हिरासत में लिया गया और 10-15 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि झड़प में पांच पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

चांदनी महल पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, यह घटना रात करीब 12.40 बजे घटी जब निषेधाज्ञा के बावजूद भीड़

तुर्कमान गेट के पास जमा हो गई और पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगी। कारंटबल संदीप ने अपनी शिकायत में कहा कि पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिए बार-बार घोषणाएं करके भीड़ को तितर-बितर होने के लिए कहा, लेकिन समूह ने कथित तौर पर आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया।

प्राथमिकी में लिखा है, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए थे और तुर्कमान गेट पर करीब 30 से 35 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जो पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रही थी। इसमें कहा गया, हालांकि, भीड़ ने निर्देशों का पालन नहीं किया और नारे लगाना जारी रखा, बैरिकेड तोड़ दिए और दंगा करने लगी।

ईडी ने जेपी 'धोखाधड़ी' मामले में 400 करोड़ की संपत्ति जब्त की

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर के पूर्व प्रबंध निदेशक मनोज गोड से जुड़े एक ट्रस्ट और संपत्तियों के खरीद-फरोख्त के काम से जुड़ी कंपनी 'इन्वेस्टर्स क्लिनिक' के प्रवर्तक हनी कटियाल की कंपनी की कुल 400 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की गई यह कार्रवाई जेपी समूह की कंपनियों - जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जेआईएल) और जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएल) - और उनसे संबंधित संस्थाओं के खिलाफ नोएडा में जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स परियोजनाओं के घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन की बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और दुरुपयोग की जांच से जुड़ी है।

भारत की योजना 2040 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अहमदाबाद/भाषा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख ए एस किरण कुमार ने बुधवार को कहा कि भारत की योजना 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की है। वर्तमान में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) की प्रबंधन परिषद के अध्यक्ष कुमार एस्ट्रोनामिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (एसआई) के 5वें सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, "अब से लेकर 2040 तक अंतरिक्ष गतिविधियों में कई मिशन चलाए जाने वाले हैं।



2040 तक हमारी योजना भारतीयों को चंद्रमा पर भेजने और उन्हें सुरक्षित वापस लाने की है। भारत 2040 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है।" पीआरएल परिसर में आयोजित कार्यक्रम के इतर मीडिया से बातचीत में इसरो के पूर्व प्रमुख ने देश के अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में विस्तार से बताया।

इसरो के नए साल का पहला प्रक्षेपण 12 जनवरी को

बेंगलूर/भाषा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 12 जनवरी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी-सी62 मिशन का प्रक्षेपण करेगा। इसरो नए साल के अपने पहले मिशन की तैयारी में जुट गया है। इसरो ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "पीएसएलवी-सी62 मिशन का प्रक्षेपण 12 जनवरी 2026 को भारतीय समयानुसार 10:17 बजे श्रीहरिकोटा स्थित एसडीएससी एसएचएआर के प्रथम प्रक्षेपण पैड (एफएलपी) से निर्धारित है।"

एमटेक और पीएचडी पाठ्यक्रम में बदलाव करेंगे आईआईटी

नई दिल्ली/भाषा। प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में एमटेक और पीएचडी पाठ्यक्रमों को आईआईटी परिषद की बैठक के बाद नया रूप दिया जाना तय है। अधिकारियों का दावा है कि इन कार्यक्रमों द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। देश के 23 प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों की सर्वोच्च समन्वय संस्था, आईआईटी परिषद ने यह निर्णय पिछले वर्ष अगस्त में हुई अपनी बैठक में लिया। यह बैठक दो वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद आयोजित की गई थी। जेआईएड एडवांस्ड परीक्षा को एक बेहतर और कम तनावपूर्ण मूल्यांकन वाला बनाने के उद्देश्य से, आईआईटी परिषद ने परीक्षा को अनुकूल बनाने की संभावना तलाशने की सिफारिश की, जिसमें उम्मीदवार की क्षमता के अनुसार प्रश्न वास्तविक समय में स्वतः तैयार किए जाएंगे।

‘तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को आयात घटाना और निर्यात बढ़ाना होगा’

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि अगर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, तो उसे आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने पर खास ध्यान देना होगा। गडकरी ने सीएसआईआर के ‘प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समारोह’ को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि अपशिष्ट (एगो-वेस्ट) को उपयोगी संसाधन में बदला जा सकता है, जिससे न केवल किसानों को फायदा होगा बल्कि कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता भी कम की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में पेट्रोलियम-रहित घटक



बायो-बिंदुमेन का इस्तेमाल ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की दिशा में एक रूपांतरकारी कदम है। गडकरी ने कहा, एगो-वेस्ट के उपयोग से पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण घटेगा और संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल पर आधारित अर्थव्यवस्था को

मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यदि वाहन ईंधन में 15 प्रतिशत मिलावट की जाए तो भारत करीब 4,500 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा बचा सकता है और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता में बड़ी कमी आ सकती है। गडकरी ने कहा कि फिलहाल दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भारत को तीसरे स्थान पर पहुंचने के लिए अपना आयात घटाने और निर्यात को बढ़ाने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि भारत व्यावसायिक स्तर पर बायो-बिंदुमेन का उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे, ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मंत्री ने बायो-बिंदुमेन के इस्तेमाल को इस्तेमाल पर आधारित अर्थव्यवस्था और

पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार वृद्धि की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया। गडकरी ने कृषि और निर्माण उपकरण विनिर्माताओं से वैकल्पिक ईंधन और फ्लेक्स-इंजन आधारित वाहनों को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने बताया कि सरकार ने हरित भारत को तीसरे स्थान पर पहुंचने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में 10 राजमार्ग खंड चिन्हित किए हैं। लेकिन उन्होंने हाइड्रोजन ईंधन के परिवहन को एक बड़ी चुनौती बताया। गडकरी ने कहा कि भारत को ऊर्जा का आयातक नहीं, बल्कि निर्यातक बनना चाहिए। गडकरी ने कहा कि देश हर साल करीब 22 लाख करोड़ रुपए जीवाश्म ईंधन के आयात पर खर्च करता है, जिसकी वजह से प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है।

‘अंतरिक्ष संस्थानों का नेतृत्व संभालने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए’

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



अहमदाबाद/भाषा। भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान (आईआईए) की निदेशक प्रोफेसर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम ने बुधवार को कहा कि भारतीय अंतरिक्ष संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन उन्हें नेतृत्व संभालने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आईआईए की पहली महिला निदेशक प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने यहां भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) में आयोजित ‘एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी ऑफ इंडिया’ (एसआई) की पांचवीं संगोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि महिलाओं को संस्थागत और पारिवारिक स्तर पर अधिक समर्थन की जरूरत है। उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, अंतरिक्ष अन्वेषण में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के

साथ भारत लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व स्तर पर उनकी उपस्थिति अभी कम है। प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने कहा कि लचीले कार्य घंटों जैसी सहायक संगठनात्मक नीतियां अधिक से अधिक महिलाओं को अपना करियर जारी रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। उन्होंने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पर बात करते हुए कहा कि देश अपने प्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधनों का लगभग 50 प्रतिशत खोने का जोखिम नहीं उठा सकता और देश की बेहتری के लिए महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं में शामिल किया जाना चाहिए।

मॉरीशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखूल ने तिरुपति मंदिर में पूजा-अर्चना की

तिरुपति/भाषा। मॉरीशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखूल ने बुधवार को तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की। टीटीडी के अधिकारियों ने गोखूल का स्वागत किया और उन्हें मंदिर में दर्शन के लिए ले गए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “गोखूल ने भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए। इससे पहले टीटीडी के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें दर्शन के लिए ले गए थे।” दर्शन के बाद, टीटीडी के अधिकारियों ने उन्हें (मॉरीशस के राष्ट्रपति को) रंगनायकुला मंडपम में रेशमी वस्त्र, प्रसाद और भगवान वेंकटेश्वर की एक तस्वीर प्रदान की। टीटीडी तिरुपति में स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर का आधिकारिक संस्कृत निकाय है।

मुख्यमंत्री अब्दुल्ला जरूरी मुद्दों पर चुप हैं, पीडीपी की आलोचना में व्यस्त हैं : महबूबा मुप्ती



दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

श्रीनगर/भाषा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुप्ती ने बुधवार को केंद्रशासित प्रदेश के लोगों से जुड़े मुद्दों पर चुप्पी साधने को लेकर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा।

महबूबा ने अपने पिता एवं पीडीपी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद की दसवीं पुण्यतिथि पर दिए गए संक्षिप्त भाषण में कहा कि महबूबा उनकी पार्टी (पीडीपी) के प्रति जरूरत से ज्यादा चुप हैं और अपना ज्यादातर समय केवल उसकी आलोचना करने में ही व्यस्त रहते हैं।

महबूबा मुप्ती ने कहा, “आज, यदि कोई युवा अपनी बात रखता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। हजारों लोग (विभिन्न) जेलों में बंद हैं। जब मैं इन मुद्दों को लेकर अदालत गई तो मुझे कहा गया कि मैं कौन होती हूँ इस पर बोलने वाली। यदि हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा?” मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, “यह उमर की जिम्मेदारी थी, मेरी नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता वह (मुख्यमंत्री) अपने 50 विधायकों और कई सांसदों के साथ किस दुनिया में रहते हैं कि वह इन मुद्दों पर बात ही नहीं करते? वह सिर्फ पीडीपी की आलोचना करते हैं, वह पीडीपी के प्रति चुप हैं।”

भारत की जीडीपी वृद्धि अगले वित्त वर्ष में 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान: रिपोर्ट

मुंबई/भाषा। विदेशी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन शेक्स ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, जो चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 7.3 प्रतिशत दर से कम होगा। हालांकि, सरकार की तरफ से बुधवार को जारी राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। गोल्डमैन शेक्स की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई बढ़ने की आशंका को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास आगे ब्याज दरों में कटौती की सीमित गुंजाइश बचेगी। रिपोर्ट कहती है, हमें वर्ष 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026-27 में 6.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने वाले निजी पूंजीगत व्यय या नए निवेश पिछले कुछ वर्षों में सुस्त रहे हैं। इसके अलावा वर्ष 2025 में अमेरिका की ओर से लगाए गए उच्च शुल्क का भी पूंजीगत व्यय पर असर पड़ा।

सरकार का फरवरी में संसद में बीज विधेयक पेश करने का लक्ष्य: कृषि सचिव



नई दिल्ली/भाषा। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार ने बजट सत्र के पहले चरण में फरवरी में संसद में बीज विधेयक 2025 पेश करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “हमें बीज विधेयक 2025 के लिए सुझावों सहित 9000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हम इन पर विचार करेंगे और ‘कैबिनेट नोट’ में इन्हें शामिल करेंगे। हमारा लक्ष्य इस विधेयक को बजट सत्र के पहले चरण में पेश करना है।”

सचिव ने कहा कि मंत्रालय संसद के अवकाश के बाद कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 को पेश करने की योजना बना रहा है। बीज विधेयक, 1966 के बीज अधिनियम का स्थान लेगा। इसमें गुणवत्ता और पैकेट पर क्यूआर कोड जैसे आधुनिक मानकों के साथ ‘ट्रेसबिलिटी’ सुनिश्चित करने के लिए बीज किस्मों, डीलर और उत्पादकों के लिए अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान है। इसमें निगरानी के लिए केंद्रीय एवं राज्य बीज समितियों की स्थापना का भी प्रावधान है। साथ ही किसानों को बिना पंजीकरण के कृषि में संरक्षित बीजों को रखने और आदान-प्रदान करने की अनुमति दी गई है। व्यक्तिगत तौर पर उल्लंघनों के लिए जुर्माना एक लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक से लेकर कारावास तक हो सकता है। यह मामले की गंभीरता के आधार पर लगाया जाएगा। इसमें तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है।



आंध्र प्रदेश : टोल प्लाजा के निकट बस में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोयलूर (आंध्र प्रदेश)/भाषा। विशाखापत्तनम जा रही एक बस में बुधवार तड़के पूर्वी गोदावरी जिले के गमन ब्रिज टोल प्लाजा के निकट आग लग गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। चालक की सूझबूझ से बस में सवार सभी 10 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को वाहन के आग की चपेट में मंशा जताई।

लिया गया। पुलिस के अनुसार, बस जब रात लगभग दो बजे टोल प्लाजा के निकट पहुंची, तभी उसमें आग लग गई। एक पुलिस अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, इस घटना में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर चालक का कहना है कि डायनामो में आई तकनीकी खराबी के कारण आग लगी। टोल प्लाजा के निकट बस रोकने के बाद चालक ने इंजन की जांच की, जहां उसे चिंगारियां दिखाई दीं। इसके

बाद उसने तुरंत यात्रियों और कर्मचारियों को सतर्क किया, जो तुरंत निकट में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर चालक का कहना है कि डायनामो में आई तकनीकी खराबी के कारण आग लगी। टोल प्लाजा के निकट बस रोकने के बाद चालक ने इंजन की जांच की, जहां उसे चिंगारियां दिखाई दीं। इसके



प्रतिशत और चार प्रतिशत उत्तरदाताओं के लिए कारण रहे। रिपोर्ट कहती है कि विदेशी प्रवास को लेकर भारतीयों की

पसंद में भी बदलाव आ रहा है। करीब 52 प्रतिशत लोगों ने समय के साथ अपनी पसंदीदा जगह बदली है, जबकि 43 प्रतिशत ने

अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए स्पष्ट प्राथमिकता जताई। जर्मनी 43 प्रतिशत लोगों की पसंद के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद ब्रिटेन 17 प्रतिशत, जापान नौ प्रतिशत और अमेरिका चार प्रतिशत लोगों की पसंद रहा। विदेश जाने की इच्छा रखने वाली भारतीय नर्सों के रुझान में क्षेत्रीय विविधता भी देखने को मिली। विदेश जाने वाली 61 प्रतिशत नर्सें प्रमुख महानगरों से बाहर से संबंधित हैं जबकि दिल्ली-एनसीआर से 17 प्रतिशत नर्सों ने विदेश जाने की बात कही। हालांकि, करियर एवं पैसे के

लिए विदेश जाने की राह में चुनौतियां बनी हुई हैं। भाषा की जरूरतों को 44 प्रतिशत लोगों ने सबसे बड़ी बाधा बताया। इसके अलावा, अनैतिक भर्ती, मार्गदर्शन का अभाव, अधिक खर्च और लंबी प्रक्रियाएं भी प्रमुख समस्याओं के रूप में उभरीं। टर्न ग्रुप के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अविनव निगम ने कहा, भारतीय प्रतिभा वैश्विक करियर के लिए तैयार है लेकिन इसके लिए पारदर्शी, नैतिक और शुल्क-शुल्क वाली भर्ती व्यवस्था जैसे समर्थनकारी कदम उठाने की जरूरत है।

बेहतर करियर के लिए 52% भारतीयों ने जताई विदेश जाने की मंशा : रिपोर्ट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि बेहतर करियर एवं पैसे कमाने के लिए युवाओं में भारत से विदेश जाने का मजबूत रुझान देखा गया है। सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक प्रतिभागियों ने विदेश जाने के बारे में मंशा जतायी।

एआई-सक्षम वैश्विक प्रतिभा आवाजाही मंच टर्न ग्रुप के हाल के एक सर्वेक्षण में 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विदेश जाने पर

विचार करने या इसकी सक्रिय तैयारी करने की बात कही। यह सर्वेक्षण देशभर में करीब 8,000 लोगों से बातचीत पर आधारित है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय विकास भारत से बाहर जाने का सबसे बड़ा कारण बनकर उभरा। करीब 46 प्रतिशत लोगों ने इस वजह से विदेश जाने की मंशा जताई। इसके बाद बेहतर करियर की तलाश के लिए 34 प्रतिशत लोग विदेश जाने को तैयार दिखे। इसके अलावा व्यक्तिगत सपने और वैश्विक अनुभव भी क्रमशः नौ

वैज्ञानिकों ने एआई आधारित मॉडल बनाया, नींद के आंकड़ों से बीमारी के खतरे का लगायेगा पता



दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। अनुसंधानकर्ताओं ने कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल करके एक मॉडल बनाया है जो नींद के आंकड़ों से 100 से अधिक अलग-अलग स्वास्थ्य स्थिति के खतरे का अनुमान लगा सकता है। एक शोध में इसकी जानकारी दी गई है। इस मॉडल को ‘स्लीपएफएम’ नाम दिया गया है, जिसे अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं समेत अन्य लोगों ने मिलकर बनाया है। इस अनुसंधान में 65,000 लोगों ने हिस्सा लिया और उनसे एकत्र किए गए करीब छह लाख घंटे के नींद के आंकड़ों पर इसे प्रशिक्षित किया गया है। ‘नेचर मेडिसिन’ नामक पत्रिका में छपे एक पेपर में बताया गई इस कृत्रिम मेधा प्रणाली को शुरू में नींद के विश्लेषण से जुड़े मानक कार्यों पर परखा गया था, जैसे नींद के अलग-अलग चरण को रिकार्ड करना या स्लीप एपनिया की गंभीरता का पता लगाना। इसके बाद इस मॉडल का इस्तेमाल नींद के आंकड़ों का विश्लेषण करके भविष्य में होने वाली बीमारी का अनुमान लगाने के लिए किया गया, जिसमें हेल्थ रिकार्ड का डेटा एक स्लीप क्लिनिक से लिया गया था। अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि स्वास्थ्य रिकार्ड में 1,000 से ज्यादा बीमारियों की श्रेणी रखी गई और मरीज के सोने के आंकड़ों

का इस्तेमाल करके 130 बीमारियों का अंदाजा सटीकता से लगाया जा सका। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ‘मनोरोग एवं व्यवहार विज्ञान’ विभाग में स्लीप मेडिसिन के प्रोफेसर और सीनियर लेखक इमैनुएल मिग्रोट ने कहा, “जब हम नींद का अध्ययन करते हैं तो हम बहुत सारे सिग्नल रिकॉर्ड करते हैं। यह एक तरह की जंगल फिजियोलॉजी है जिसका हम एक ऐसे व्यक्ति पर आठ घंटे तक अध्ययन करते हैं जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होता है। इसमें बहुत सारा डेटा होता है।” पॉलीसोमनोग्राफी – जिसे नींद के अध्ययन में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है – नींद का डेटा इकट्ठा करने का एक आम तरीका है जो सेंसर का इस्तेमाल करके दिमाग की एक्टिविटी, दिल के काम, सांस के सिग्नल और आंखों की हरकतों के साथ-साथ दूसरी चीजों को रिकॉर्ड करता है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि एआई मॉडल कई तरह के डेटा को शामिल करने में सक्षम था – जैसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी (दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी), एल्ट्रा सोनोग्राफी (मांसपेशियों की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी), पल्स रीडिंग और सांस लेने का एयरफ्लो – और यह पता लगाने में कि वे एक-दूसरे से कैसे जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि एआई प्रणाली के अनुमान केंसर, प्रेग्रेसी की दिक्कतों, सर्कुलेटरी बीमारियों और मेटल डिसऑर्डर के लिए खास तौर पर बहुत अच्छे पाए गए।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हाथेरी। कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता के रूप में बुधवार को इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने वाले सिद्धरामय्या ने कहा कि वह जनता के आशीर्वाद से राजनीति में यहां तक पहुंचे हैं और उन्हें नहीं पता कि यह कितने समय तक सक्रिय रहेंगे। सिद्धरामय्या ने रेखांकित किया कि जब तक उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा, तबतक राजनीति में बने रहेंगे। उन्होंने अपने प्रशासन के कामकाज को लेकर भी संतोष जताया।

मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में कांग्रेस नेता सिद्धरामय्या (77) ने 2,792 दिनों के साथ राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का

देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा, 'राजनीति में बने रहने के लिए जनता का आशीर्वाद होना जरूरी है। जनता के आशीर्वाद से ही मैं यहां तक पहुंचा हूँ, आगे कितने समय तक राजनीति में रहूँगा, यह नहीं जानता। मैं यहां तक आया हूँ और आज भी सक्रिय रहूँगा। जब तक जनता का आशीर्वाद रहेगा, तब तक राजनीति में बना रहूँगा।'

कर्नाटक की मुख्य विपक्षी भारतीया जनता पार्टी (भाजपा) ने सिद्धरामय्या की उपलब्धियों को शून्य बताते हुए दावा किया है कि राज्य का खजाना खाली है। इस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के नेता झूठ बोलने में माहिर हैं और वे ऐसा करते रहते हैं।

सिद्धरामय्या ने सवाल किया, 'एससीपी/टीएसपी (विशेष घटक योजना और जनजातीय उप-योजना) अधिनियम कौन लाया? क्या इसे वे (भाजपा) लाये? क्या उन्होंने पदोन्नति में आरक्षण दिया? अन्न भाग्य योजना किसने शुरू की? वे कैसे कह सकते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया? उन्हें जनता से पूछना चाहिए कि हमने क्या किया-यह है।'

सिद्धरामय्या का राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का अनूठा रिकॉर्ड ऐसे समय में सामने आया है जब सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष तेज हो गया है।

राज्य में मुख्यमंत्री परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही हैं। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 20वीं नवंबर को अपने पांच साल के कार्यकाल का आधा समय पूरा कर लिया है। सिद्धरामय्या और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के बीच 2023 में हुए 'कथित सत्ता-साझाकरण' समझौते ने इस अटकलों को और हवा दी।

चीनी मिल के बॉयलर में विस्फोट, दो लोगों की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हुबली। कर्नाटक में हाल में सरकारी अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार की गई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक महिला पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनसे दुर्यवहार किया था। हालांकि, पुलिस ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। हालांकि, पुलिस का दावा है कि महिला ने खुद अपने कपड़े उतारे और पुलिसकर्मीयों पर हमला भी किया। महिला द्वारा काटे जाने से उन्हें चोटें भी आईं।

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने इस घटना के लिए महिला को दोषी ठहराया, जबकि भाजपा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसकी पार्टी पदाधिकारी को निर्यस्त किया। घटना एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे निवादा खड़ा हो गया। हुबली-धारावाड़ के पुलिस आयुक्त एन शशिकुमार ने बुधवार को महिला के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि महिला ने खुद न केवल अपने कपड़े उतारे बल्कि दो

उप-निरीक्षकों समेत चार पुलिस अधिकारियों को काट भी दिया। सुत्रों के अनुसार, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए राजस्व अधिकारी पुलिसकर्मीयों के साथ उस स्थान पर गए थे, जहां कर्मित तौर पर अशुद्ध रूप से कब्जा करने वालों ने उन पर हमला कर दिया।

इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था और महिला मुख्य आरोपी हैं। पुलिस का दावा है कि जब पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो महिला ने गिरफ्तारी का विरोध किया। पुलिस की टीम ने महिला को जबरदस्ती पुलिस वाहन में बैठाया। महिला ने आरोप लगाया है कि पुलिस टीम ने उसे निर्यस्त किया। इस आरोप का खंडन करते हुए शशिकुमार ने पत्रकारों को घटनाक्रम से अलग कर दिया। उन्होंने बताया कि हुबली के केशवापुर के चालुय्य नगर इलाके में जब सरकारी अधिकारी भूमि संयोजन के लिए पहुंचे तो लोग उनका प्रतिरोध करने लगे और उन पर हमला कर दिया।

इस संबंध में मामले दर्ज किए गए हैं जो जांच अधिकारी के शामिल एक महिला का फैसला किया। इस कि गिरफ्तारी के दौरान उसने अत्यंत संयम और उन्होंने लगभग अधिकारियों और का लिया क्योंकि उन्हें आशंका थी।

अधिकारी ने कहा कि जब महिला को पुलिस गया तो उसने खुद दिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों और व लोगों की मदद ली। ईतना कि महिला ने बार-बार महिला का अनुरोध किया।

शशिकुमार ने कहा कि आरोपों का और लया गया आ और लया दुर्घटनापूर्ण है। मैंने घटनाक्रम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को सिद्धरामय्या को 'सबसे अधिक कर्ज लेने वाले मुख्यमंत्री' करार दिया और उन खबरों का हवाला दिया जिनमें कहा गया है कि राज्य सरकार जनवरी से मार्च तक की चौथी तिमाही में 93,000 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। सिद्धरामय्या द्वारा कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का इतिहास रचे जाने पर विपक्ष में कर्ज को लेकर उनकी आलोचना की। सिद्धरामय्या वित्त मंत्रालय का प्रभारी भी संभाल रहे हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार पर कर्नाटक को पीछे 'धकेलने' का आरोप लगाते हुए कहा कि सिद्धरामय्या को यह सम्पन्नता चाहिए कि इतिहास केवल कार्यवाली की अवधि को महत्व नहीं देता बल्कि उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत के आधार पर उनका मूल्यांकन करता है। उन्होंने कहा, सिद्धरामय्या सचिं सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नहीं बल्कि सबसे अधिक कर्ज लेने वाले मुख्यमंत्री भी हैं।

अशोक ने 'एक्स' एक पोस्ट में कहा, आंकड़ों और विरासत में अंतर यह है कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का खिताब महज एक आंकड़ा है। सबसे अधिक कर्ज लेने वाले मुख्यमंत्री का खिताब एक विरासत है। उन्होंने कहा, इनमें से एक को भुला दिया जाया जबकि दूसरे को कर्नाटक के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जायेगा।

अशोक ने नवीनमत आंकड़ों को चौंकाने वाला बताते हुए कहा, एक ही तिमाही में 93,000 करोड़ रुपये का कर्ज, भारत में चौथी तिमाही में लिया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा कर्ज होगा। इसे शासन नहीं कहा जा सकता, यह खराबट है कि गए वित्तीय प्रबंधन की सटीक परिभाषा है।

भाजपा नेता के अनुसार, यह कर्ज में भारी वृद्धि राजकोषीय ढांचे के पतन के कारण हुई है, जिनमें पिछले ऋणों को चुकाने के लिए उपभोग लेना, अस्थिर गादरी योजनाओं को खतरनाक रूप से वित्तपोषित करने के लिए उपहार लेना और बुनियादी आर्थिक नियंत्रण की विफलता के कारण नकदी प्रवाह में भारी गिरावट आना शामिल है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बैंगलूर। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को बलारी क्षेत्र की पुलिस उप महानिरीक्षक वार्तिका कटियार, आईपीएस (केएन 2010) का तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय में पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में रित्त पद पर तबादला किया जाता है।

अधिसूचना के अनुसार, पी एस हर्षा, आईपीएस (केएन 2004), जो पदस्थान की प्रतीक्षा कर रहे थे, को तत्काल प्रभाव से ऑर अगले आदेश तक बलारी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के रूप में वार्तिका कटियार के स्थान पर तैनात किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है, सुनदी प्रेक्षक, आईपीएस (केएन 2013), पुलिस उपयुक्त, खुफिया विभाग, का तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक बलारी जिला पुलिस अधीक्षक के रित्त पद पर तबादला किया जाता है।

एक जनवरी की रात बलारी के कुछ इलाकों में उस वक्त तनाव व्याप्त हो गया था, जब बलारी शहर के विधायक नारा भरत रेड्डी और गंगावती क्षेत्र के विधायक जी जगनदेन रेड्डी के समर्थकों के बीच चर्चा से जुड़े एक मुद्दे पर झड़प हुई।

झड़प के दौरान कथित पथराव और गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना के बाद, सरकार ने नेजुर को निलंबित कर दिया, जिन्होंने एक जनवरी को ही बलारी पुलिस अधीक्षक का पदभार संभाला था। उन्हें इस आधार पर निलंबित किया गया था कि उन्होंने स्थिति को ठीक से नहीं संभाला और विरिष्ठ अधिकारियों को जमीनी हालात के बारे में उपयुक्त जानकारी नहीं दी। विपक्षी भाजपा ने सरकार पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को “बलि का आरोप बकरा” बनाने का आरोप लगाया है।

यूपी-निरीक्षकों समेत चार पुलिस अधिकारियों को कार में भी लिया। सूत्रों के अनुसार, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए राजस्व अधिकारी पुलिसकर्मियों के साथ उस स्थान पर गए कि, जहां कथित तौर पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों ने उन पर हमला कर दिया। इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था और महिला मुख्य आरोपी है। पुलिस का दावा है कि जब पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो महिला ने गिरफ्तारी का विरोध किया। पुलिस की टीम ने महिला को जबरदस्ती पुलिस वाहन में बंधाया। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस टीम ने उसे निर्बन्ध किया। इस आरोप का खंडन करते हुए शशिकुमार ने पत्रकारों को घटनाक्रम से अवगत करया। उन्होंने बताया कि हुबहली के केशापुर के चालुय्य नगर इलाके में जब सरकारी अधिकारी भूमि सर्वेक्षण के लिए पहुंचे तो लोग उनका प्रतिरोध करने लगे और उन पर हमला कर दिया।

अलग-अलग
में से एक मामले
(और) ने एक भाग
गिरफ्तार करने
कुमार ने बताया
कि गुरु अधिकारी
साथानी बर्ती।
में से 10 महिला
में को अपने साथ
ही होने की पूरी
इसके बावजूद,
महान में हो जाया
होने काफ़े उजा
हमारी महिला
में से स्थानीय
दरसे वक़्त का

संवाददाताओं से कहा कि आरोपी महिला ने पुलिस अधिकाřियों को काट लिया था। उन्होंने कहा, “जब पुलिस अधिकाřियों महिला को गिरफ्तार करने गए तो उसने कई अधिकाřियों को काट लिया। यह बहुत बुरी बात है। उसके खिलाफ

प्रथमिकी दर्ज की गई थी। जब पुलिसकर्मी उसने गिरफ्तार करने गए तो उसने उन्हें पीटा और काट लिया।

सिद्धरामय्या ने कहा कि किसी को भी कार्रवाई अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा विधायक आर अशोक ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की। अशोक ने सोशल मीडिया चॅनल 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, हबली केशवापुर पुलिस द्वारा कांग्रेस पार्टी के एक नगर निकाय सदस्य की शिकायत पर भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता को निर्वस्त्र करके पीटने की अमानवीय घटना, राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा बेशर्मी से चलाई जा रही नफरत की राजनीति का एक और उदाहरण बन गई है, जो खुद को शर्मिंदा करने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के तहत कर्नाटक में विपक्षी विधायकों की हत्या के प्रयास, विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले और अत्याचार जैसे अपराधिक घटनाएँ आम होती जा रही हैं। अशोक ने आरोप लगाया, "मुष्टमंजी सिद्धरामय्या नीत कांग्रेस सरकार ने राज्य में अधोपिप्त आपातकाल लगा दिया है।"

भारत सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बायोटेक्नोलॉजी विभाग
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद (ब्रिक)
(बायोटेक्नोलॉजी विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय)

सूचना

दिनांक 22 सितंबर – 28 सितंबर, 2025 के रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन संख्या सीबीसी 36301/11/0007/2526 का संदर्भ लें।

उपरोक्त विज्ञापन के उत्तर में बहुत कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसलिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने तथा सबसे योग्य व्यक्ति का चयन करने के लिए प्रतिनियुक्ति के तहत निम्नलिखित 6 पदों के लिए इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए समान नियम एवं शर्तों के साथ विज्ञापन पुनः प्रकाशित किया गया है:

i. निदेशक (प्रशासन)	– 1 पद
ii. निदेशक (वित्त)	– 1 पद
iii. अनुभाग अधिकारी	– 4 पद

जिन अभ्यर्थियों ने उपरोक्त पदों के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन पत्र तथा अन्य विवरण निम्नलिखित वेबसाइटों : www.dbtindia.gov.in, www.bric.nic.in पर उपलब्ध हैं।

CBC 36301/11/0010/2526

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ
Karnataka Chalanachitra Academy

ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಮೃತೋತ್ಸವ ಭವನ ಸಂಕೀರ್ಣ, ನಂ. 20/ಎ,
ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560096. ದೂರವಾಣಿ: 080-23493410
ಇ-ಮೇಲ್: chalanachitraacademy@gmail.com

ಸದ. ಕಛೇರಿ/17ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾದರವಿ/ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇ-ಮೇಲ್/28/2025-26 ದಿನಾಂಕ: 06.01.2026

**17ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ
ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲು
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ**

17ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ
ಮಾದರಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ
ತನುಲುವ ವೆಚ್ಚದ ಕುರಿತಂತೆ KTPP ಕಾಯ್ದೆ 1999 ಮತ್ತು KTPP ನಿಯಮಗಳ
2000ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು
ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಕೋಡಿಯಾದ ಅರ್ಹ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇ-
ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್‌ಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ
ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ <https://kppp.karnataka.gov.in> ನಲ್ಲಿ
ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ದಿನಾಂಕ: 06.01.2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆ
ನಂತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಇಎಂಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 18,750/- (ರೂ. ಹದಿನೆಂಟು
ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ಐವತ್ತು ಮಾತ್ರ)ಗಳನ್ನು ಇ-ವೇಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ
ದಿನಾಂಕ : 14.01.2026 ರ ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಅರ್ಹತೆ ಪರಶ್ರುಗಳ
ವಿವರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್
<https://kppp.karnataka.gov.in> ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
+91-080-46010000, +91-080-68948777ನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಛೇರಿ
(080- 23493410)ಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಟೆಂಡರ್‌ನ ಅಂದಾಜು
ಮೊತ್ತ ರೂ. 15.00 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಸಹಿ/-
ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್

DIPR/CPISA/4916/2025-26

 **ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ**
Karnataka Chalanachitra Academy
ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಮ್ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭವನ ಸಂಕೀರ್ಣ, ನಂ. 20/ಎ,
ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560096. ದೂರವಾರ್ತೆ: 080-23493410
ಇ-ಮೇಲ್: chalanachitraacademy@gmail.com

ಸದ. ಕಛೇರಿ/17ನೇ ಬಿ.ಎಂ.ಸಿ/ಬಿ.ಎಂ.ಸಿ/ದೂರವಾರ್ತೆ, ಇ-ಮೇಲ್/31/02/25-26 ದಿನಾಂಕ: 06.01.2026

**17ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ
ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇಂ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಿಸೆ**

17ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚದ ಕುರಿತಂತೆ KTPP ಕಾಯ್ದೆ 1999 ಮತ್ತು KTPP ನಿಯಮಗಳು 2000ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಹ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇಂ-ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಹಕ್ಕಾಸಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ <https://kppp.karnataka.gov.in> ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ದಿನಾಂಕ: 06.01.2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇಂ-ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಇಎಂಐ ಮೊತ್ತ ರೂ. 16,000/- (ರೂ. ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ)ನ್ನು ಇ-ಇಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ: 14.01.2026 ರ ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಅರ್ಹತೆ ಪರಶ್ವಗಳು ವಿವರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ <https://kppp.karnataka.gov.in> ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ದೂರವಾರ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: +91-080-46010000, +91-080-68948777ನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಛೇರಿ (080-23493410)ಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಟೆಂಡರ್‌ನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 12.80 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಸಹಿ/-
ರಿಸಪಾನ್ಸ್

सुविचार

अपने पैरो पे खड़े होकर
मरना, निचे गिरकर ज़िन्दगी
जीने से बेहतर है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

जंक फूड का जाल

ब्रिटेन ने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए जंक फूड के संबंध में जो सख्ती दिखाई है, उससे अन्य देशों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत में जंक फूड का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसे जीवन स्तर से जोड़कर देखा जाने लगा है। टीवी और सोशल मीडिया पर प्रसारित विज्ञापनों ने परिवारों की सोच को इस कदर बदल दिया है कि जंक फूड को आधुनिक जीवन की अनिवार्यता समझा जाने लगा है। कुछ लोग इसके पैकेट पर लिखी मात्रा को पढ़कर सोचते हैं कि इससे हमें पर्याप्त पोषण मिल जाएगा, जबकि यह धारणा सही नहीं है। कई लोग पश्चिमी देशों की हर चीज को महान समझ लेते हैं। वे पश्चिमी नाम, खानपान, रहन-सहन, पहनावे आदि को अपनाने में बड़प्पन महसूस करते हैं। बात जब खानपान की हो तो याद रखना चाहिए कि हमारे देश की भौगोलिक स्थिति, मौसम, फसल चक्र, जलवायु बिल्कुल अलग हैं। अगर हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर पश्चिमी देशों का खानपान अपनाएंगे तो रोगी होंगे। नब्बे के दशक में टीवी पर ऐसे विज्ञापनों की भरमार शुरू हुई थी, जिनमें बच्चों को बताया जाता था कि स्कूल जाने से पहले यह चीज खाएंगे तो आपका दिमाग तेज चलेगा, यह चीज पीएंगे तो शरीर में बिजली दौड़ेगी। बच्चों की एक किताब में 'विकास' का बड़ा विचित्र वर्णन किया गया था। एक लेखक राजस्थान के गांव में बतौर मेहमान जाता है तो उसे नाश्ते में ब्रेड परोसी जाती है! यह देखकर लेखक कहता है कि अब राजस्थान के गांव पिछड़े नहीं रहे, ये विकास करने लगे हैं!

अगर नाश्ते में ब्रेड की जगह बाजरे की रोटी, चटनी और छाछ परोसी जाती तो इन्हें पिछड़ेपन से जोड़कर देखा जाता। यह कितना हास्यास्पद है! ब्रेड खाना या बाजरे की रोटी खाना किसी व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे देश के भोजन को पिछड़ेपन से जोड़कर देखना उचित नहीं है। अब तो वैज्ञानिक भी स्वीकार करने लगे हैं कि बाजरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। भारत सरकार श्री अन्न का प्रचार कर रही है। हमारे देश को खानपान के मामले में स्वर्ग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहां हजारों प्रकार के पकवान हैं। चटनी, अचार, शर्बत और अन्य पेय पदार्थों की तो गिनती ही नहीं है। हर मौसम के लिए अलग चीजें हैं। उनके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण हैं। कौनसा पदार्थ किस मौसम में खाने से फायदा देगा और कब नुकसान करेगा, इसका वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। क्या जंक फूड के समर्थन में कोई ऐसा प्रमाण है? अब डॉक्टर इससे दूर रहने के लिए कह रहे हैं। फिर भी ब्याह-शादियों से लेकर सामान्य दिनों में भी लोग जंक फूड खाने के लिए उमड़ते हैं। उसे पचाने के लिए ऊपर से खास किस्म के शीतल पेय पीते हैं। कई बच्चों को इनकी लत लग चुकी है। वे दाल, सब्जी, रोटी और सलाद से दूर भागते हैं। दूध, दही, पनीर, छाछ देखकर उनकी भूख गायब हो जाती है। हां, वे जंक फूड खाने के लिए आधी रात को उठने को तैयार हैं। बच्चों को ऐसे विज्ञापन बहुत आकर्षित करते हैं, जिनमें बताया जाता है कि एक चीज कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। सवाल है- समय की इतनी बचत करने के बाद क्या करेंगे? मोबाइल फोन चलाएंगे? बच्चों को स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खानपान संबंधी अच्छी आदतें सिखाएं। जंक फूड से जितना दूर रहें, उतना बेहतर है। अपने देश का शुद्ध और सात्विक खानपान सर्वश्रेष्ठ है।

ट्वीटर टॉक

प्रदेश में बालिका शिक्षा के हाल इतने बेहाल हैं कि सरकार की लेटेलतीथी और अनिर्णयों के कारण कॉलेज आयुक्तालय प्रदेशभर की छात्राओं को समय पर स्कूटी नहीं दे पा रहा है। 2024-25 और 2025-26 के लिए निकाला गया टेंडर भी निरस्त कर दिया गया है।

—गोविंदसिंह डोटारसा

खारी नदी में बजरी डंपर से हुई मौत एक हृदयविदारक घटना है, जो भाजपा सरकार के संरक्षण में पनप रहे बजरी माफिया के खुले कल का प्रमाण है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। बजरी माफिया बेलागाम हैं और भाजपा सरकार उनकी संरक्षक बनी हुई है।

—अशोक गहलोत

मुंबई में आयोजित जैन आचार्य, पद्म भूषण श्री रत्नसुंदर सूरिधर जी महाराज के साहित्यिक योगदान पर आधारित ऊर्जा 500 महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज जब विश्व में शांति की आवश्यकता है।

—ओम बिरला

प्रेरक प्रसंग

पारखी दृष्टि

एक बार की बात है, एक कला प्रेमी ने महान इतालवी मूर्तिकार माइकल एंजेलो से उनकी विश्वप्रसिद्ध 'डेविड' की मूर्ति को देखकर आश्चर्य से पूछा- महोदय, आपने पत्थर के एक साधारण और बेजान टुकड़े से इतनी जीवंत और सुंदर मूर्ति का निर्माण कैसे किया? यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। माइकल एंजेलो ने मुस्कुराते हुए बहुत ही खूबसूरत उत्तर दिया, 'मैंने कोई निर्माण नहीं किया। यह मूर्ति तो पहले से ही उस पत्थर में विद्यमान थी। मैंने तो बस पत्थर के उस अनावश्यक हिस्से को छेनी-हथौड़े से काट कर हटा दिया, जो मूर्ति नहीं था। जैसे ही मैंने पत्थर से फालतू परतों को हटाया, उसमें मूर्ति के रूप में छिपा उसका सत्य अपने आप प्रकट हो गया।' माइकल एंजेलो ने दार्शनिक अंदाज में उस कला प्रेमी से कहा-जीवन का भी यही सार है। हमें पूर्णता पाने के लिए बाहर से कुछ नया नहीं जोड़ना है, बल्कि अपने भीतर छिपे क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या रुपी अनावश्यक पत्थरों को हटाना है। तभी हमारा श्रेष्ठ स्वरूप निखरकर सामने आएगा।

सामयिक

जब पहचान ही अपराध बन जाए

नूपेन्द्र अभिषेक नूप
मोबाइल - 9955818270

हाल-फिलहाल बांग्लादेश में जिस प्रकार की लश्कित हिंसा देखने को मिल रही है, वह सामान्य कानून-व्यवस्था की विफलता से कहीं अधिक गहरी और चिंताजनक समस्या की ओर संकेत करती है। जो स्थिति प्रारंभ में आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से उपजे असंतोष के रूप में सामने आई थी, वह अब धीरे-धीरे पहचान-आधारित घृणा, संस्थागत निष्क्रियता और सामाजिक विश्वास के क्षरण में बदलती दिखाई दे रही है। देश के विभिन्न जिलों से सामने आ रही हत्याओं, हमलों और धमकियों की घटनाएं यह स्पष्ट करती हैं कि हिंसा अब अराजक या आकस्मिक नहीं रही, बल्कि वह चयनित, सुनियोजित और विशेष समुदायों व व्यक्तियों को निशाना बनाकर की जा रही है। यह प्रवृत्ति बांग्लादेशी समाज की दिशा और राज्य की उस क्षमता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है, जिसके तहत वह अपने सभी नागरिकों को समानता और सुरक्षा देने के संवैधानिक वादे को निभाने के लिए बाध्य है। इस हिंसा की पृष्ठभूमि उस लंबे दौर के असंतोष से जुड़ी है, जिसकी शुरुआत राजनीतिक सुधारों और आर्थिक जवाबदेही की मांगों के साथ हुई थी। बीते एक वर्ष में शासन की विफलताओं, बढ़ती महंगाई, रोजगार के अवसरों की कमी और भ्रष्टाचार के आरोपों के विरुद्ध हुए आंदोलनों ने राज्य की नींव को हिला दिया। समय के साथ ये आंदोलन अपना केंद्रीकृत नेतृत्व और स्पष्ट दिशा खोते चले गए। इसी शून्य का लाभ उठाकर चरमपंथी प्रवृत्तियों, आपराधिक गिरोहों और अवसरवादी तत्वों को खुला मैदान मिल गया। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह अराजकता अब उन लोगों पर हमलों के रूप में सामने आ रही है, जिन्हें उनके कर्मों के कारण नहीं, बल्कि उनकी पहचान के कारण निशाना बनाया जा रहा है, विशेषकर धार्मिक अल्पसंख्यकों, छोटे व्यापारियों और उन व्यक्तियों को, जिन्हें सामाजिक या राजनीतिक रूप से कमजोर समझा जाता है। हालिया घटनाएं इस भयावह वास्तविकता को और स्पष्ट करती हैं। कम समय के भीतर सामने आए कई मामलों में यह पाया गया कि पीड़ितों की हत्या उनकी धार्मिक या सामुदायिक पहचान की पुष्टि के बाद की गई। छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और यहां तक कि सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों पर ऐसे हमले हुए, जिनसे यह प्रतीत होता है कि ये कृत्य अज्ञान के उभरे क्रोध का परिणाम नहीं, बल्कि पहले से सोचे-समझे और योजनाबद्ध अपराध थे। एक घटना में एक व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि कुछ ही समय पहले पास के जिले में एक अन्य व्यवसायी को इसी तरह गोली मार दी गई थी। एक अन्य मामले में एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पहले सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई और इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर प्रसारित किया गया। यह न केवल क्रूरता को दर्शाता है, बल्कि समाज में भय फैलाने और हिंसा को सामान्य बनाने की सोची-समझी कोशिश भी प्रतीत होती है। ये घटनाएं अलग-थलग नहीं हैं, बल्कि उस व्यापक पैटर्न का हिस्सा हैं, जो तब उभरता है जब राज्य की सत्ता कमजोर पड़ जाती है और जवाबदेही की व्यवस्थाएं ढहने लगती हैं। इतिहास गवाह है कि राजनीतिक संक्रमण या अस्थिरता के दौर में अल्पसंख्यक समुदाय अक्सर आसान निशाना बन जाते हैं। बांग्लादेश में भी यह प्रवृत्ति पहले देखी जा चुकी है, लेकिन वर्तमान दौर इसलिए अधिक खतरनाक है क्योंकि इसमें हिंसा की तीव्रता और आवृत्ति दोनों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। विशेष रूप से हिंदू नागरिकों को बार-बार निशाना बनाए जाने से व्यापक भय का वातावरण बन गया है और लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि क्या केवल नागरिक होना ही सुरक्षा की गारंटी देने के लिए पर्याप्त है। इस स्थिति को और गंभीर बनाने वाला एक पहलू अंतरिम प्रशासन की स्पष्ट निष्क्रियता या अक्षमता है। यद्यपि सरकारी बयान इन घटनाओं की निंदा करते हैं और जांच का आश्वासन देते हैं, लेकिन धरातल पर ठोस परिणाम बहुत कम दिखाई देते हैं। गिरफ्तारियां यदि होती भी हैं तो प्रायः देर से, और दोषसिद्धि तो और भी दुर्लभ है। यह विफलता केवल प्रशासनिक नहीं है; यह अपराधियों को यह संदेश देती है कि वे बिना किसी भय के हिंसा कर सकते हैं। जब न्याय में देरी होती है या वह मिलता ही नहीं, तब हिंसा एक अपवाद न रहकर सत्ता और नियंत्रण का साधन बन जाती है, जिसके माध्यम से असहमति और भिन्नता को दबाया जाता है। इस हिंसा की जड़ें जटिल और आपस में जुड़ी

नजरिया

गिग-वर्कर्स की परेशानियों को समझना आवश्यक

बेहद कम मेहनताने, कंपनी मालिकों के दबाव व ग्राहकों की उपेक्षा झेलते गिग वर्कर्स ने नये साल की पूर्व संध्या पर हड़ताल करके अपनी बदहाली को ही उजागर किया है। संवेदनशील कार्य परिस्थितियों और नौकरी की असुरक्षा के चलते गिग-वर्कर्स हड़ताल पर थे। हालांकि, नये साल पर काम के दबाव व पूरी तरह संगठित न होने के कारण इनकी हड़ताल का कुछ ही इलाकों में असर देखा गया। पूरे देश में सामान की आपूर्ति बाधित हुई हो,ऐसी कोई खबर नहीं मिली। गिग वर्कर्स की समस्या यह है कि वे किन कंपनियों के लिए काम करते हैं, उनके वे कर्मचारी नहीं माने जाते। गिग-वर्कर्स की प्रमुख मांग है कि उनके काम का बेहतर भुगतान हो और उनके लिये बेहतर कामकाजी परिस्थितियां बनायी जाएं। उनकी इस हड़ताल ने इन मुद्दों पर देश का ध्यान खींचा है। गिग वर्कर्स यूनियनों का दावा है कि 31 दिसंबर को देश भर में 2 लाख से ज्यादा डिलीवरी राइडर्स ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया। गिग वर्कर्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नौ पांच की पक्की नौकरी के बजाय अस्थायी, लचीले समय अवधि वाले या फ्रीलान्सर के रूप में काम करते हैं। जौमेटो, स्विगी, ब्लिंकित आदि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के डिलीवरी पार्टनर्स या ओला, उबर जैसे कैब प्लेटफॉर्म के लिये काम करने वाले लोग गिग वर्कर्स ही कहलाते हैं। इन्हें हर काम के लिए अलग-अलग पैमेंट मिलता है। ये लोग कंपनी के पक्के कर्मचारी नहीं होते। इसलिए इन्हें नियमित वेतन, भत्ते, या अन्य कर्मचारी लाभ नहीं नियमित वेतन, भत्ते, या अन्य कर्मचारी लाभ जैसे पेंशन, छुट्टी नहीं देना पड़ता है। ऐसे वर्कर्स जितना काम करते हैं, उतना मेहनताना मिलता है। भारत की गिग इकॉनमी में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वित्त वर्ष 2024-25 तक लगभग 12 मिलियन गिग श्रमिकों का अनुमान है, जो सत्र 2020-21 में लगभग 7.7 मिलियन था। भारत की गिग इकॉनमी श्रम बाजार का एक प्रमुख हिस्सा बनकर उभरी है। बीते दिनों नववर्ष की पूर्व संध्या पर ऐप-आधारित डिलीवरी और परिवहन क्षेत्र से जुड़े हजारों श्रमिकों द्वारा की गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल ने सुविधा आधारित अर्थव्यवस्था के पीछे छिपी कठोर वास्तविकताओं को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। यह विरोध इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि गिग श्रमिक भारत के शहरी

दैनिक सेवाओं के लिए कितने महत्वपूर्ण बन चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गिग वर्कर्स कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनमें आय की अनिश्चितता, नौकरी की असुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, और एल्गोरिदम आधारित दबाव प्रमुख हैं, जिससे उन्हें कम वेतन और कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, और इन पर तत्काल सरकारी नियमन और बेहतर कानूनी परिस्थितियों की जरूरत है, जैसा कि हालिया हड़तालों से पता चला है, ताकि उनका शोषण रुके और उन्हें न्याय मिले। पिछले दिनों आप के राघव चड्ढा और राजन के मनोज कुमार झा जैसे सांसदों ने गिग वर्कर्स के शोषण का मुद्दा संसद में उठाया था। निरसंदेह, देश की गिग अर्थव्यवस्था ने रोजगार सृजन में अपनी क्षमता साबित की है। गिग वर्कर्स की समस्याएं इसलिए और बढ़ गई हैं, क्योंकि दस मिनट में भी सामान की डिलीवरी करने का चलन जोर पकड़ गया है। इस चलन पर फिर से विचार होना चाहिए, क्योंकि इससे गिग वर्कर्स के साथ दुर्घटनाएं होने का जोखिम बढ़ गया है। कई बार गिग वर्कर शीघ्र सामान पहुंचाने के फेर में ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन करते दिखते हैं। निःसंदेह गिग वर्कर बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें मिलने वाले मेहनताने को आकर्षक नहीं कहा जा सकता। डिलिवरी समय-सीमा और सड़क सुरक्षा के बीच संबंध को साबित करने के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन समस्या इतनी गंभीर हो गई थी कि बेंगलूरु पुलिस ने इस पर ध्यान दिया और डिलिवरी कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। वहां की पुलिस ने यह कदम तब उठाया जब उसने लापरवाह ड्राइविंग के कारण डिलिवरी पार्टनर्स को खिलफा बुकिंग और जुर्माने में उल्लेखनीय वृद्धि

देखी। इसलिए, गिग श्रमिकों की यह मांग कि इन समय-सीमाओं को समाप्त किया जाए, निराधार नहीं है। सत्र 2020-21 में प्लेटफॉर्म आधारित कामों में 77 लाख श्रमिक लगे थे और अनुमानतः सत्र 2029-30 तक इनकी संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ होने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार के साथ उन कंपनियों को भी उनकी सुधि लेनी होगी, जिनके लिए वे काम करते हैं। उन्हें केवल सामाजिक सुरक्षा के ही दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए, बल्कि ऐसे उपाय भी किए जाने चाहिए, जिससे उनका शोषण न हो सके और वे अपने भरपूर पोषण लायक आय अर्जित कर सकें। इस पर भी ध्यान दिया जाए कि सामान की डिलीवरी के लिए बेंटरी चालित दोपहिया वाहनों का ही उपयोग हो। यह भी समय की मांग है कि गिग वर्कर्स के साथ असंगठित क्षेत्र के अन्य सभी कामगारों के हित की भी चिंता की जाए। यह ठीक नहीं कि लाखों अस्थायी कामगार सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गिग इकॉनमी आज तीव्र विस्तार और श्रम न्याय की तात्कालिक आवश्यकता के बीच एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। गिग वर्कर्स की कमाई अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर निर्भर है। ग्राहक के घर से रेस्टोरेंट की दूरी के आधार पर इनकी कमाई तय होती है। इस संबंध में पीएआईजीएमए और पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध के आंकड़ों कहते हैं, लगभग 50 फीसदी डिलीवरी कर्मचारी प्रतिदिन 201-600 रुपये कमाते हैं, जबकि लगभग 43 फीसदी कैब-आधारित गिग वर्कर रोजाना 500 रुपये से कम कमाते हैं। विंडेबना यह है कि खूब काम लेने के बावजूद गिग-वर्कर्स को पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारियों के दायरे से बाहर आजीविका कमाने वाले

व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेकिन नियोक्ताओं की हायर व फायर की रणनीति के चलते, वे असुरक्षित कार्य परिस्थितियों में काम करने को बाध्य होते हैं। इसके बावजूद वे आज शहरी जीवन व्यवस्था के लिये अभिन्न अंग बन गए हैं। लोगों की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दौड़ते रहते हैं। वे सामान दस मिनट तक दूरगार पर पहुंचाने के दबाव में हांफते-भागते, मोटरसाइकिल दौड़ाते और सीढ़ियों पर सामान चढ़ाते अक्सर नजर आते हैं। आम तौर पर उपभोक्ताओं का व्यवहार भी अच्छा नहीं होता। देरी होने पर इन्हें झिड़का जाता है। सामान में नुकस निकालकर इन्हें दौड़ाया जाता है। निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की अनदेखी नहीं की जा सकती। लेकिन किलहल स्थिति यह है कि मेहनताने में कटौती, जरा सी चूक पर आर्थिक दंड तथा समय से पहले पहुंचाने के दबाव से गिग-वर्कर्स त्रस्त हैं। मुश्किल परिस्थितियों में काम करते रहने के बावजूद ये कामगार हड़ताल में बड़ी संख्या में भाग नहीं ले पाए। दरअसल, प्लेटफॉर्म अक्सर प्रोत्साहन और अतिरिक्त वेतन के जरिये श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन को दबा देते हैं। नीति आयोग के वर्ष 2024 के एक सर्वेक्षण ने खुलासा किया कि 90 फीसदी गिग श्रमिकों के पास बचत नहीं है। प्लेटफॉर्म के कुछ व्यवहार जैसे छुट्टी लेने वाले कर्मियों को डिस्कनेक्ट करना, उनकी आय की अस्थिरता को और बढ़ा देते हैं। हड़ताल की धमकी के जवाब में, कुछ एप्पीगैटर ने क्रिसमस और वर्षात के दौरान प्रोत्साहन भुगतान बढ़ा दिए। निश्चित रूप से गिग-वर्कर्स का लगातार 14 घंटे काम करने के बावजूद सात-आठ सौ रुपये कमाना और दुर्घटना बीमा से वंचित रखना, इस व्यवस्था की उन खामियों की ओर भी इशारा करता है, जिन्हें केवल फौरी लालच या प्रोत्साहन से ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसे में हालिया श्रम सुधारों का महत्व बढ़ जाता है। जिसमें पहली बार, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को कानून के तहत औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है। एप्पीगैटर के टर्नओवर का एक से दो फीसदी सामाजिक सुरक्षा कोष में अनिवार्य योगदान और आधार से जुड़े सार्वभौमिक खाता नंबर को कानूनी मान्यता की दिशा में एक लंबे समय से प्रतीक्षित बदलाव का संकेत देते हैं। लेकिन बात तब बनेगी, जब इस प्रस्ताव के प्रावधानों को सही तरह लागू करने में सफलता मिलेगी।

प्रदर्शन



कोलकाता में बुधवार को 'आशा' वर्कर्स ने कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ 'धेराव' आंदोलन के तहत विरोध प्रदर्शन किया।

अपहरण के बाद बच्ची की हत्या

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। बेंगलूरु के पूर्वी हिस्से में स्थित व्हाइटफील्ड इलाके के पास छह साल की बच्ची का अपहरण कर उसकी हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक पीड़िता पश्चिम बंगाल के एक प्रवासी मजदूर की बेटी थी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के पिता ने बेटी

के पांच जनवरी की दोपहर से लापता होने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई और उसने नजदीक ही रह रहे पश्चिम बंगाल के एक मजदूर की संलिप्तता का संदेह जताया। पीड़िता के पिता ने बताया कि उसे उक्त व्यक्ति पर संदेह है क्योंकि जहां पर बच्ची खेल रही थी वहां पर उसे देखा गया था। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक बेटी के लापता होने पर परिवार ने उसकी तलाश शुरू की और बाद में पुलिस को इसकी सूचना दी। बच्ची का शव

बाद में पड़दूर अग्रहारा के पास एक सूखे नाले में मिला। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई। पुलिस के अनुसार यौन उत्पीड़न के संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस ने बताया कि हत्या के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। परिवार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है और संदिग्ध को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।

मन की पवित्रता से ही जीवन आगे बढ़ता है : साध्वी भव्यगुणाश्री

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। शहर के वीवी पुरम में विराजित साध्वी भव्यगुणाश्रीजी ने कहा कि मन को नियंत्रण कर लो, जीवन सुधर जाएगा। यह मन ही तो है जो पाप, पुण्य कराता है, जीवन को नेक और अनेक रास्तों पर ले जाता है इसलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन की जीते जीता। मन की पवित्रता से जीवन आगे बढ़ता है, क्योंकि जीवन में मन ही है जो स्वयं भटकता है और जीवन को भी भटकता है। यदि वह अपने वश में हो जाता है तो सब कुछ सही रहता है। जीवन का उत्थान होता है। जिंदगी केवल तीन धांस की है। पहली धांस जन्म की, दूसरी धांस है जवानी की और तीसरी बुढ़ापे की। इसके बाद जीवन खत्म हो जाता है। इस अवसर पर साध्वी शीतलगुणाश्रीजी ने कहा कि दिल



बड़ा, दिमाग ठंडा, जुबान मीठी अपने दिल को बड़ा रखें, अपने दिमाग को हमेशा ठंडा रखें और अपनी जुबान को हमेशा मीठी बनाए रखें। जिसके पास इन सद्गुणों की दोलात है दुनिया में उससे ज्यादा सुखी-उससे बड़ा धनवान और कोई नहीं। भगवान महावीर ने हमें ढाई हजार साल पहले यह मंत्र दिया था कि तुम औरों पर नहीं, अपने आप पर अनुशासन करना सीख लो। विहार सेवा का लाभ अनेक श्रावक श्राविकाओं ने लिया।



माहेश्वरी महिला संगठन ने दो आश्रम में बांटी राशन सामग्री

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। मकरसंक्रांति के उपलक्ष्य में मानवीय सेवा कार्य के तहत माहेश्वरी महिला संगठन ने शहर के दो आश्रम में दो माह की राशन सामग्री का सहयोग दिया। संगठन ने तवरकरे स्थित साई

स्नेहधामा वृद्धाश्रम जिसमें 170 मूक-बधिर बच्चे, लड़के, लड़कियां, वृद्ध महिलाएँ, पुरुष हैं तथा दूसरा सेंट थॉमस टाउन में स्थित स्नेहदीप ट्रस्ट फॉर दि डिसेबल आश्रम में जिसमें 60 दृष्टिहीन लड़के लड़कियां हैं को

खाद्य सामग्री भेंट की। इस सेवा कार्य में अध्यक्ष धेता बियाणी, विजय लक्ष्मी सारड़ा, गायत्री मालपानी, बिमला चांडक, बिन्दु गिलड़ा, नम्रता मिलक, सुमित्रा चांडक सहित अनेक सदस्याएँ उपस्थित थीं।

मानव सेवा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत



बेंगलूरु के महावीर इंटरनेशनल बेंगलूरु सेंटर के सदस्यों ने मंगलवार रात्रि को सज्जनराव सर्कल के आसपास 500 जरूरतमंदों को ठंड से राहत पाने के लिए कंबल एवं गर्म टोपी का वितरण किया। संस्था के अध्यक्ष विजयराज सिसोदिया, मुख्य सचिव आशिक पिरगल ने कहा कि मानव सेवा ही सभी साधना है। संस्था सदैव करुणा, सेवा और समाज कल्याण के मार्ग पर अग्रसर रहने का प्रयास करेगा। सदस्यों ने सभी दानदाताओं के प्रति आभार जताया तथा अपने हाथों से जरूरतमंदों को कम्बल व टोपी का वितरण किया।

श्रद्धांजलि



अनंतनाग में बुधवार को पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती अपने पिता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी पर उनकी कब्र पर श्रद्धांजलि देने के जाती हुई।

इन्फोसिस ने उद्यम स्तर पर सृजनात्मक एआई अपनाने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज के साथ साझेदारी की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/नई दिल्ली। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी इन्फोसिस ने उद्यम स्तर पर सृजनात्मक कृत्रिम मेधा (जेनरेटिव एआई) को बढ़ावा देने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) के साथ रणनीतिक साझेदारी की बुधवार को घोषणा की। इस सहयोग के तहत इन्फोसिस की एआई पेशकश 'इन्फोसिस टोपाज' और एडब्ल्यूएस का सृजनात्मक एआई आधारित टूल 'अमेजन क्यू

डेवलपर' एक साथ काम करेंगे। इस सहयोग का मकसद न सिर्फ इन्फोसिस के आंतरिक कामकाज को अधिक कुशल बनाना है, बल्कि विनिर्माण, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में ग्राहकों के लिए नए समाधान एवं नवाचार को गति देना भी है। इन्फोसिस टोपाज, जेनरेटिव एआई प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं, समाधानों और मंचों का एक समूह है, जबकि अमेजन क्यू डेवलपर एक ऐसा एआई असिस्टेंट है जो सॉफ्टवेयर विकास और उद्यम स्तर पर कामकाज में मदद करता है। एडब्ल्यूएस के भारत एवं दक्षिण

एशिया क्षेत्र के अध्यक्ष संदीप दत्ता ने एक बयान में कहा कि अमेजन क्यू और इन्फोसिस टोपाज की मिली-जुली ताकत से कंपनियों को नवाचार करने, कामकाज में फुर्ती लाने और ग्राहकों के लिए बेहतर मूल्य सृजन में मदद मिलेगी। इन्फोसिस के कार्यकारी उपाध्यक्ष बालकृष्ण डी. आर. ने कहा कि यह साझेदारी उद्यम मूल्य के सृजन और उसे ग्राहकों तक पहुंचाने के तरीके को बदल रही है। उन्होंने कहा कि इससे विकास चक्र के साथ मानव संसाधन, भर्ती और आपूर्तिकर्ता प्रबंधन जैसे अहम कार्यों में भी बदलाव संभव होगा।



मनोज कुमार सिंह व इश्वंदर सिंह

इश्वंदर सिंह फिर बने फिग्स की नए अध्यक्ष व मनोज सिंह बने महासचिव फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनाइट एवं स्टोन इंडस्ट्री की नई कार्यकारिणी गठित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनाइट एवं स्टोन इंडस्ट्री (फिग्स) की साधारण सभा बुधवार को एक होटल में आयोजित हुई। सभा में वर्ष 2026-28 के लिए फिग्स की नई कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया जिसमें एक बार फिर इश्वंदर सिंह को फिग्स के अध्यक्ष पद की तथा मनोज कुमार सिंह को महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रमोद भंडारी को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा अरुण मलहोत्रा, गुरु शास्त्रीमठ, सुन्दर सोमानी, कलित भंडारी, डॉ हरपाल सिंह यादव व एस. शंकरनारायण को उपाध्यक्ष, राकेश राठी को सहकोषाध्यक्ष, श्रीमती अजिता जाय, कैलाशसिंह मेरतिया, मनीष पोद्दार, जांकी चक्कीवाला, युसूफ कमल खान, नरेश कुमार बंसल, दीपक वी. पटेल व देवेन्द्रकुमार सोनी को सहमंत्री बनाया गया है। इस मौके पर फिग्स के नए अध्यक्ष इश्वंदर सिंह ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि नई कमेटी के साथ मिलकर हम नवचार, कौशल विकास, संस्था की सुदृढ़ता एवं नए बाजार की खोज के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि फिग्स की प्राकृतिक पथर की आपूर्ति में अग्रणी स्थान पाएँ ऐसा हमारी टीम का प्रयास रहेगा। नए महासचिव मनोज कुमार सिंह ने भी सभी को साथ लेकर उद्योग की नई उचाइयों को प्राप्त करने का संकल्प दोहराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में फिग्स के अनेक सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने नई कमेटी के पदाधिकारियों का सम्मान किया तथा उन्हें बधाइयां दी।

डिजिटल रूप में भी पढ़ें
दक्षिण भारत हिन्दी दैनिक

www.dakshinbharat.com



व्यावर संघ का स्नेह मिलन 11 को, तैयारियां जोरों पर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के ब्यावर संघ का आगामी रविवार को स्नेह मिलन आयोजित है। बुधवार को स्नेह मिलन की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। चेयरमैन अरविन्द खिचसरा

और अध्यक्ष पदमचंद बोहरा ने बताया कि इस बार का स्नेह मिलन गोल्डन पॉम रिसॉर्ट में आयोजित है। महामंत्री अरविन्द कोठारी ने बताया कि इस आयोजन में बेंगलूरु में निवास कर रहे ब्यावर के करीब साढ़े पांच सौ परिवारों के सदस्यों के शामिल होने की संभावना है। सहमंत्री ललित डाकलिया ने बताया कि स्नेह मिलन में विभिन्न

मनोरंजक प्रतियोगिताएँ, खेलकूद कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। आगामी कार्यकाल हेतु चुनाव अधिकारी पन्नालाल कोठारी के नेतृत्व में नए अध्यक्ष का चुनाव भी किया जाएगा। कोषाध्यक्ष विनेश लोढ़ा व कार्यकारिणी सदस्यों के साथ ब्यावर युवा शाखा और महिला विंग के सदस्य तैयारियों में जुटे हुए हैं।

जीसी सेन्टर में एसबीआई की नई शाखा का हुआ शुभारंभ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चन्ना श्रीनिवासुलु सेड्डी ने बेंगलूरु सर्कल की मुख्य महाप्रबंधक जूही स्मिता सिन्हा एवं अन्य महाप्रबंधकों की उपस्थिति में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) सहित कुल 11 शाखाओं का उद्घाटन किया। यह पहल किसी भी भारतीय बैंक द्वारा भारत में समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना की दिशा में अपनी तरह का पहला प्रयास है। एसबीआई ने जीसीसी के लिए एक समर्पित संबंध प्रबंधन टीम भी गठित की है, ताकि उनकी विशिष्ट बैंकिंग आवश्यकताओं की



पूर्ति की जा सके और निर्बाध सेवा प्रदान की जा सके। वहीं बैंक ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत कर्नाटक राज्य के विभिन्न जिलों में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के उन्नयन, आईआईएससी मेडिकल स्कूल के भागवी

पार्थसारथी अस्पताल के ईएनटी विभाग में नैदानिक एवं चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति, तुमकुर विश्वविद्यालय के न्यू केंपस में 50,000 वृक्षारोपण अभियान और मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप (एमईजी) एवं सेंटर ऑफ़ ई-एम्बुलेंस की आपूर्ति में सहयोग किया है।